जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 15 संख्याः 133 प्रभात चूरू, रविवार 10 सितम्बर, 2023 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

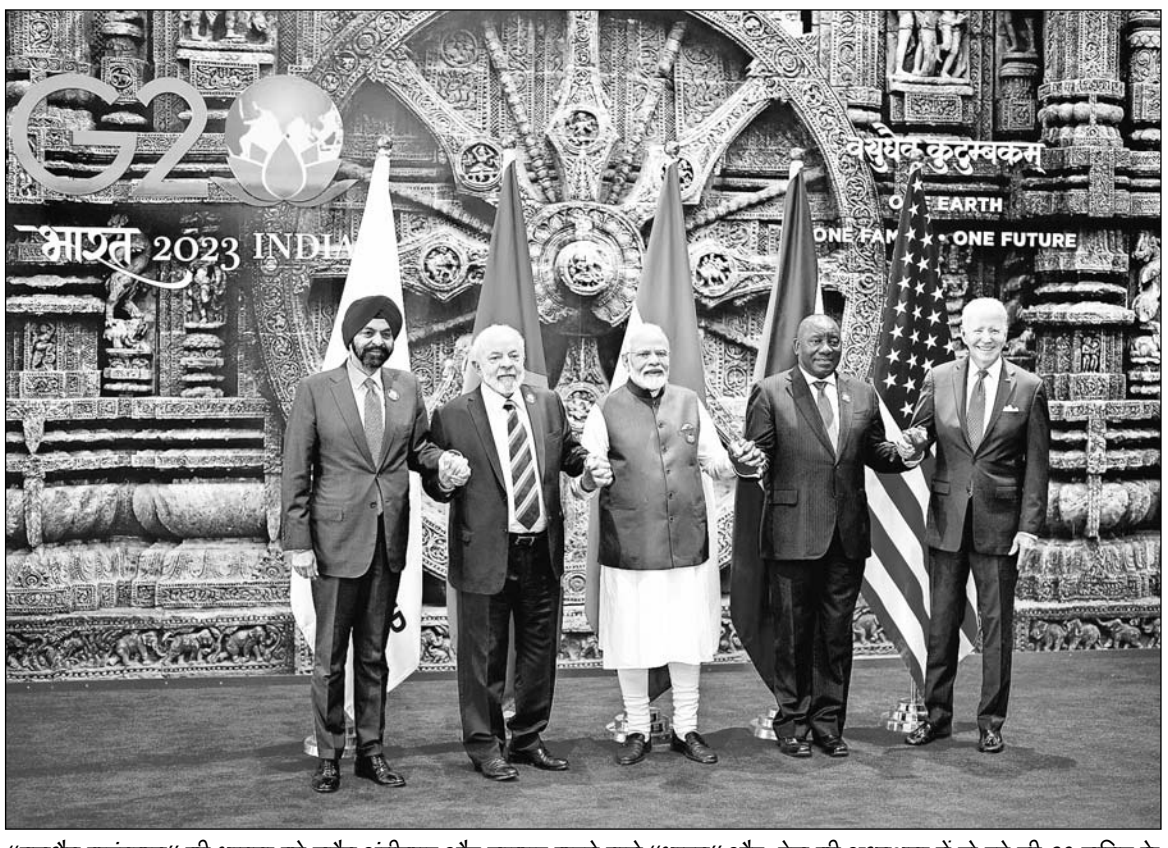

''वसुधैव कुटुंबकम'' की भावना को सदैव अंगीकार और साकार करने वाले ''भारत'' और देश की अध्यक्षता में हो रहे जी-20 समिट के आयोजन में शनिवार को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई, साउथ अफ्रीकी यूनियन भी दुनिया के इस सबसे ताकतवर संगठन का सदस्य बन गया। गौरतलब है कि, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दक्षिण अफ्रीका से वादा किया था और साउथ अफ्रीकी यूनियन को इस संगठन की सदस्यता दिलाने का व्यक्तिगत तौर पर बीड़ा उठाया था। दक्षिण अफ्रीका ने जी-20 संगठन में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा है कि, अब से पहले दुनिया के बड़े हिस्से और बड़ी आबादी को इस तरह के अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण मंचों से दूर रखा गया था, लेकिन भारत की अध्यक्षता के दौरान जो कदम उठाए गये हैं वे कदम दुनिया को सही दिशा देने में अहम् भूमिका निभायेंगे। दिल्ली में नवनिर्मित भारत मण्डपम में शनिवार दोपहर को जी-20 बैठकों का दौर शुरु हो गया। आयोजन स्थल में ही शाम को जी-20 नेताओं का ग्रैण्ड डिनर रखा गया है, जिसमें देश और दुनिया के 170 से अधिक राजनेता और शीर्ष संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। ऊपर दी गई तस्वीर हैंडशेक मोमेंट की है जिसमें (बांए से दांए) वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा व अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन नज़र आ रहे हैं।

नई दिल्ली घोषणा पर जी-20 देशों की सहमति, भारत की भारी कूटनीतिक जीत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 के पहले दिन इस संबंध में घोषणा की और इसे ''गुड न्यूज़'' बताया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज घोषणा की कि जी-20 में नेताओं की घोषणा के लिए सर्वसम्मति हो गई है। प्रधानमंत्री ने जी-20 सम्मेलन के पहले दिन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, ''एक खुशखबरी है कि सभी के सहयोग से नई दिल्ली जी-20 के नेतृत्व की घोषणा में सर्वसम्मति हो गई है।

नई दिल्ली जी-20 नेतृत्व घोषणा पर सर्वसम्मति होना भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। भारत जी तोड़-कोशिश कर रहा था कि संयुक्त घोषणा में यूक्रेन के उल्लेख पर विभाजन न हो। घोषणा पत्र में 38 पृष्ठ और 75 परिच्छेद हैं। कई दिनों की अटकलबाजियों और आलोचनाओं के बाद जी-20 सम्मेलन नई दिल्ली जी-20 नेताओं की घोषणा को अंगीकृत कर लिया गया। इस बड़े विकास का कई नेताओं और अधिकारियों ने स्वागत किया और कहा कि यह ऐतिहासिक दस्तावेज़ मानव केन्द्रित वैश्वीकरण पर नरेन्द्र मोदी के रूझान को मान्यता देता है।

- **इस घोषणा पत्र को भारत की भारी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है, क्योंकि भारत की कूटनीतिक टीम ने यूक्रेन युद्ध पर रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के कठोर रूख को नरम बनाने में सफलता प्राप्त की है।**
- **भारत की कोशिश थी कि, यूक्रेन वॉर के मुद्दे पर जी-20 के सदस्य देशों में मत विभाजन ना हो और न ही रूस के खिलाफ कोई कड़ी टिप्पणी की जाए।**
- **रूस के खिलाफ कठोर टिप्पणी रूकवा कर, भारत अपने पुराने मित्र के साथ मित्रता निभाने में सफल रहा है।**
- **पश्चिमी देशों द्वारा रूस के विरोध का दबाव बनाए जाने पर भारत ने कहा कि, जी-20 का निर्माण विश्व की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए हुआ था, हमें उसी पर ध्यान रखना चाहिए।**

घोषणा में कहा गया है कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है और इस प्रकार यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध का उल्लेख टाल दिया गया और मॉस्को की प्रत्यक्ष आलोचना नहीं हुई। वैश्विक संगठन ने केवल यूक्रेन में समग्र, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की बात की और सदस्य देशों को याद दिलाया कि वे सीमा के अधिग्रहण के लिए शक्ति के प्रयोग या उसकी धमकी से बचे।

गत वर्ष इंडोनेशिया में हुए सम्मेलन की तर्ज पर जी-20 घोषणा एकदम स्पष्ट है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का हवाला दिया गया है जिससे यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा की गई है। गत वर्ष फरवरी में यूक्रेन पर जो हमला हुआ था, उसका 38 पृष्ठ के इस दस्तावेज में केवल तीन बार उल्लेख

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जी-20 की दिल्ली घोषणा भारत के सुपर पावर बनने का संकेत

पश्चिम के भारी दबाव के बावजूद भी संयुक्त घोषणा में रूस विरोधी टिप्पणी शामिल नहीं होने दी भारत ने

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। भारत ने जी-20 नेताओं के सम्मेलन के बाद, रूस के यूक्रेन युद्ध से पैदा होने वाले भू-राजनैतिक मुद्दों को बाईपास करते हुये, एक सर्वसम्मत घोषणा तैयार करके एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। भारत ने कहा था कि प्राथमिक रूप से जी-20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जहां विश्व के भू-राजनैतिक मुद्दों को संबोधित किया जाये।

- **भारत का तर्क था कि, जी-20 का गठन जिओ-पोलिटिकल मुद्दों के समाधान के लिए नहीं हुआ था।**
- **भारत ने याद दिलाया कि, 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की समीक्षा करने व आर्थिक मसलों के प्रबंधन के लिए जी-20 का गठन हुआ था।**
- **बताया जाता है कि, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली घोषणा में रूस की निंदा शामिल कराना चाहते थे।**

याद दिला दें कि जी-20 की परिकल्पना एक साझा मंच पर विश्व के समक्ष मौजूद आर्थिक मुद्दों का सर्वसम्मत समाधान करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में की गई थी। आलोचक तथा पश्चिमी सूत्र भले ही यह कहें कि यह उपलब्धि किसी ठोस कदम एवं कार्यवाही की बजाय, शब्दों तक सीमित है।

जी-20 का गठन 2008 वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद हुआ था, जब दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों एवं कार्यों का समन्वय करना जरूरी ही नहीं, बल्कि अनिवार्य हो गया था ताकि वैश्विक मंदी के घातक परिणामों एवं प्रभावों पर विजय पायी जा सके।

इसके साथ ही, इस घोषणा में रूस का नाम लिये बिना, उसकी अप्रत्यक्ष भर्त्सना भी निहित है। घोषणा में कहा गया है कि ''न्यूक्लिअर हथियारों को काम में लेने की धमकी अग्राह्य एवं अस्वीकार है।'' ज्ञातव्य है कि जब रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन ने यूक्रेन हमला किया था तो उन्होंने परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी दी थी।

''दिल्ली घोषणा'' में यह भी कहा गया है कि ''सभी देशों को अन्य सम्प्रभु देशों की राजनैतिक स्वतंत्रता या प्रभुसत्ता तथा जमीनी अखंडता के जमीनी अधिग्रहण की धमकी या धमकी के प्रयोग से बचना होगा।'' घोषणा में, भारत की सोच एवं रुख के अनुरुप, इस विचार का समर्थन किया गया है कि सभी मुद्दों का समाधान ''पूरी तरह से'' यू.एन. चार्टर के ढ़ाँचे के अंदर ही होना चाहिये।''

बाली सम्मेलन से लेकर दिल्ली घोषणा तक की जी 20 की स्थिति के बारे में पूछे गये एक सीधे प्रश्न के उत्तर में, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रुखा एवं संक्षिप्त जवाब दिया: ''बाली बाली था तथा नई दिल्ली नई दिल्ली है।'' उन्होंने कहा कि ''बाली घोषणा'' एक साल पुरानी है, जबकि ''दिल्ली घोषणा'' इस समय की है। दिल्ली घोषणा मौजूदा हालात पर प्रतिक्रिया है।

इसके साथ ही, जयशंकर ने यह भी स्वीकार किया कि विभिन्न ग्रुपों में, यूक्रेन युद्ध सहित, ज्वलंत मुद्दों के सम्बंध अलग-अलग प्रकार के विचार हैं। दिल्ली घोषणा में यूक्रेन की स्थिति का 8 पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी-सुनक गले मिले

नई दिल्ली, 9 सितम्बर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच शनिवार को यहां जी-20 सम्मेलन के दौरान अलग से द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें दोनों नेता गरम जोशी से एक-दूसरे से गले मिलते हुए भी नजर आए। मोदी और सुनक ने आज सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक की।

खड़गे को निमंत्रण नहीं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से शनिवार की रात को दिए गए भोज के लिए जी-20 के डैलिगेट्स को भेजे गए निमंत्रण पत्र का मसौदा तैयार करने वाले, विदेश मंत्रालय ने आमंत्रित जनों की सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल नहीं किया, जबकि, वे राज्य सभा में विपक्ष के नेता हैं।

- **जी-20 मेहमानों को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए रात्रि भोज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया, जबकि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। विपक्षी दलों ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया।**

कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि, जी-20 समिट के लिए विपक्ष को निमंत्रण नहीं देना देश के प्रजातंत्रिक ढांचे पर हमला है, विशेष रूप से जबकि, प्रोटोकॉल को देखते हुए, राज्य सभा में विपक्ष के नेता के रूप में खड़गे एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न विपक्षी दलों को भी आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि, दो पूर्व

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज पायलट के गढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी

राजनैतिक हल्कों में प्रियंका के इस रूख के खास अर्थ निकाले जा रहे हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव-प्रसार का शुभारम्भ आदिवासी क्षेत्र में अपनी जनसभा से किया था। और अब बारी प्रियंका गांधी की है, जो टोंक जिले के निवाई कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। यह स्थान सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है।

सचिन पायलट, जो देश के बाहर गये हुये थे, अब वापस आ गये हैं तथा वे प्रियंका गांधी के निवाई के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आज उन्होंने व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सभा स्थल का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सरकारी योजना ''इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना'' को लॉन्च करने के लिए प्रियंका गांधी की मौजूदगी सुनिश्चित कर ली है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिये 8 रू. में भोजन की थाली उपलब्ध होगी।

अशोक गहलोत ने बहुत सारी सरकारी योजनाएं लॉन्च की हैं, लेकिन रिपोर्ट ये मिल रही हैं कि, इन योजनाओं की क्रियान्विति बहुत अधिक कमज़ोर है। जैसे अनाज का वितरण, जिसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि, इस स्कीम को लेकर लोगों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यही हाल मोबाइल फोन वितरण स्कीम का है, इसमें भी फोन की क्वालिटी इतनी खराब है कि, प्राप्तकर्ताओं में इसे लेकर भारी प्रतिक्रिया हो रही। लोगों का कहना है कि, घटिया माल दिया जा रहा है।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा, लाभ की जगह नुकसान हो रहा है और इन योजनाओं से ना तो मुख्यमंत्री और ना ही गहलोत सरकार को कोई लाभ हो रहा है। कहा जा रहा है कि, मुख्यमंत्री ने अपनी सीकर यात्रा रद्द कर दी और केन्द्रीय गृह मंत्रालय पर दोष लगाया कि, दिल्ली में हो रहे जी-20 कार्यक्रमों की वजह से उन्हें अनुमति नहीं दी गई। गृह मंत्रालय ने प्रतिक्रिया में कहा है कि, मुख्यमंत्री ने चार अनुमतियाँ मांगी थीं और उन्हें सभी अनुमतियाँ दी गई थीं, इसलिए उनका आरोप निराधार है।

- **सूत्रों का कहना है कि, सभा के लिए टोंक जिले के निवाई का चयन कर प्रियंका ने स्पष्ट संकेत दिया है कि, वे पायलट को कितनी तवज्जो देती हैं।**
- **जनसभा कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री गहलोत ने सरकार के कुछ कार्यक्रम भी रखवा दिए हैं।**
- **सभा स्थल पर बने डोम में गहलोत सरकार की मनलुभावन योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है।**
- **एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि, इन मन लुभावन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद घटिया है। दोयम दर्जे की चीजें बांटी जा रही हैं, जिनसे फायदे की बजाय भारी नुकसान हो सकता है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''भारत नेम लेट''

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ''भारत'' नेम प्लेट के पीछे बैठकर जी-20 लीडर्स समिट की पहली बैठक को संबोधित किया। पारंपरिक ''इण्डिया'' नेम प्लेट का इस्तेमाल करने के बजाय, जी-20 समिट के प्रथम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के सामने देश के नाम की प्लेट पर ''भारत'' लिखा था।

पिछले सप्ताह, राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से जी-20 नेताओं को भेजे गए डिनर के निमंत्रण में ''प्रैसिडैंट ऑफ भारत'' लिखा था, जिसे लेकर काफी विवाद और अटकलबाजियाँ शुरु हो गई थीं। यह चचाएं भी शुरु हो गई थीं कि, 18 से 22 सितम्बर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में देश का नाम बदला जा सकता है।

- **जी-20 के पहले सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के सामने लगी देश की नेम प्लेट पर ''भारत'' लिखा हुआ था।**

जी-20 नेताओं ने ''मॉडर्न डे स्पाइस रूट'' को फाइनल टच दिया

ट्रेन और वॉटरवेज़ का यह कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ देगा

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। अभी चल रहे जी-20 सम्मेलन का एक लाभ है, एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा, जिसके तहत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इज़रायल और यूरोप से रेल एवं समुद्री मार्ग से भारत को जोड़ने के लिए कॉरीडोर बनाया जाएगा।

यह कॉरीडोर व्यापार परिवहन ऊर्जा स्त्रोतों और डिजिटल संपर्क को बढ़ाएगा और इसे चीन की बैल्ट एंड रोड परियोजना के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका स्वयं को विकासशील देशों विशेषकर भारत-प्रशांत क्षेत्र में वैकल्पिक भागीदार और निवेशक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा कि यह परियोजना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमैंट का ही एक घटक है। इस परियोजना की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डर लेयन ने की।

इस परियोजना में खाड़ी देशों और अरब देशों को रेल नेटवर्क से जोड़न का विचार है, जो भारत से पश्चिमी एशियाई बंदरगाहों से जहाजरानी मार्गों के माध्यम से भारत से जुड़ेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस परियोजना से अल्प और मध्य आय वाले देशों की आधारभूत ढांचे की जरूरतें पूरी करेंगी। यह मध्य-पूर्व से उठने वाली अशांति और असुरक्षा को कम करने में मदद करेगी।

रेल और जहाजरानी कॉरीडोर से विश्व का एक बड़ा भाग जुड़ सकेगा। जिससे देशों के बीच बेहतर डिजिटल संपर्क होगा और हाइड्रोजन जैसे ऊर्जा उत्पादों का बेहतर व्यापार हो सकेगा। अगले 60 दिनों में कार्यकारी समूह बन जाएंगे और समयबद्ध योजना भी पहले चरण में उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जाएगा, जिसमें निवेश की जरूरत है और जहां भौतिक आधारभूत ढांचे को दो देशों के बीच जोड़ा जा सकता है। वैश्विक आधारभूत ढांचे और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बाइडन के समन्वयक एमॉस होश्टीन ने कहा, ''इन योजनाओं को अगले साल क्रियान्वित किया जा सकता है ताकि वित्तीय प्रबंध और निर्माण आरंभ हो सके।

परियोजना की तैयारी जनवरी में आरंभ हुई थी जब व्हाइट हाउस ने इस विचार पर अपने क्षेत्रीय सहभागियों से चर्चा आरंभ की। परियोजना का एक उद्देश्य है इज़रायल को साथ लेना जिसके सऊदी अरब से राजनयिक संबंध नहीं है। अमेरिका दोनों देशों के संबंध सामान्य बनाने को प्रयासरत है।

- **इसे जी-20 शिखर वार्ता का भारत के लिए बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। इससे भारत, सऊदी अरेबिया, यू.ए.ई., जॉर्डन, इज़राइल और यूरोप से जुड़ जाएगा।**
- **भारत के प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन और यूरोपियन यूनियन की प्रैसिडैंट अर्सुला वॉन डर लेयन ने इस मैगा प्रोजैक्ट की संयुक्त घोषणा की। अमेरिका इस प्रोजैक्ट को वित्तीय मदद देगा।**
- **इस प्रोजैक्ट को चीन के बैल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। दावा है कि, इससे व्यापार और डिजिटल कनैक्टिविटी को प्रोत्साहन मिलेगा।**

आर.एस.एस. की बड़ी बैठक 14 से पुणे में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पुणे में 14 सितम्बर को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व उसके संबंधित संगठनों की समन्वय बैठक होने जा रही है, जिसके केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राजनैतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक में 26 संबंधित संगठन शामिल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **केन्द्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इस तीन दिवसीय बैठक में भाग लेंगे और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे।**